Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा

डॉ. राजकुमार नागवंशी*

* सह-आचार्य (अर्थशास्त्र) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – किसी देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बार-बार बदलते समय के आलोक में अपनी शिक्षा प्रणालियों और कार्यक्रमों में सुधार करते रहें है। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता को साकार करने का सर्वोत्तम साधन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4 सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के लक्ष्य को साझा करती हैं। सतत विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख तत्व के रूप में है। शिक्षा पर्यावरणीय अखंडता, आर्थिक व्यवहार्यता और न्यायपूर्ण समाज को सशक्त बनाता है, जो मानव के लिए सहायक होता है। शैक्षिक सतत विकास का उद्देश्य आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करके विकास की चुनौतियों का समाधान करता है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने जीवन में मूल्यों का विकास करता है, उनकी आकांक्षाओं को संतुलित करती है एवं साथ ही उनकी क्षमताओं को विकसित करती है । शिक्षा किसी व्यक्ति को देश का सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करती है। किसी देश की पूंजी मानव संसाधन होती है, जो शिक्षा के माध्यम से और समृद्ध होती है।

शैक्षिक रूप से कुशल नागरिकों के बिना राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की आवश्यकता और राष्ट्रीय हित के अनुसार शैक्षिक नीतियों का सुधार करे, क्योंकि समाज का भविष्य सही मूल्यों और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जो शिक्षा के माध्यम से विकसित होता है। स्वतंत्र भारत ने पहली शिक्षा नीति 1968 के दौरान पेश की गई थी एवं सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई। सन 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार 34 साल बाद वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है जो आज पुरे देश के शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में कहा जाय तो यह ज्ञान पर नहीं बल्कि वैचारिक समझ पर केंद्रित है और पाठ्यक्रम से परे व महत्वपूर्ण सोच पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रक्रिया के बजाय जुनून, अभ्यास और परिणाम-आधारित प्रदर्शन पर जोर देती है। इस प्रकार यह शिक्षा नीति वर्तमान समय की जरूरतों के अनुकूल है।

सतत विकास एवं सतत विकास लक्ष्य 2030 – सतत विकास एक ऐसे विकास की कल्पना करता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास के चार मुख्य आयाम माने जाते हैं: सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जनवरी 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद लॉन्च किए गए है, जिसमें वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए 184 सदस्यीय सरकारों और शिक्षा क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए चर्चा की गई एवं रणनीति बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें मुख्य रूप से 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए है जिसमे लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दुनिया को सही दिशा में बदलने में मदद करने के लिए सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक तत्व के रूप में रखा गया है। शिक्षा मौलिक रूप से, जीवन में सुधार, लोगों के जीवन स्तर और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक आवश्यक कारक है जिसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य किया गया है । सतत विकास के लिए शिक्षा में शिक्षण और सीखने में प्रमुख रूप से सतत विकास के प्रमुख मुद्दों को शामिल करना है। जैसे उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम में कमी, जैव विविधता, गरीबी में कमी और टिकाऊ खपत आदि। इसमें सहभागी शिक्षण और सीखने के तरीकों की भी आवश्यकता है जो शिक्षार्थियों को अपने व्यवहार को बदलने और सतत विकास के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और सशक्त करें।

सतत विकास के प्रमुख घटक

1. **सतत विकास के सामाजिक घटक:** सामाजिक घटकों में मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानवीय तत्व है। जिसमे सामाजिक अस्थिरता से सम्बंधित सभी बुराइयों को खत्म करना है इसमें सतत विकास के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता का निर्माण करना और वर्तमान समय व्याप्त में सामाजिक बुराइयों को रोकना है व खत्म करना है एवं सामाजिक स्थिरता बनाये रखना है।
2. **सतत विकास के आर्थिक घटक:** आर्थिक विकास दुनिया भर में एक लोकप्रिय नीति एजेंडा है और इसकी एक शाखा के रूप में, विकास अर्थशास्त्र एक नए अनुशासन के रूप में उभरा है। इस प्रकार कहा जाय की आज की आवश्यकतानुसार व वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में सफल होने के लिए सतत रूप से आर्थिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, आर्थिक स्थिरता आज की मुख्य आवश्यकता है साथ ही व्यापार चक्र से

निपटना व आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करना जो आज हमें सतत विकास प्रणाली इन सबका हल देता है ।

3. सतत विकास के पर्यावरणीय घटक: सतत विकास का तीसरा घटक पर्यावरण है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीनों घटक एक-दूसरे पर ओवरलैप करते हैं क्योंकि वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हर देश आज आर्थिक विकास को बढाने की होड़ में लगा है जिससे निरंतर पर्यावरण संसाधन का उपयोग से आर्थिक विकास को गति तो मोली है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अरबों टन ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्पादन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। जिसका परिणाम वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन है जो समस्त मानवीय एवं आर्थिक गतिविधिया प्रभावित हुई है एवं इसका एक ही समाधान है और वों है सतत विकास प्रणाली को प्रभावपूर्ण तरीके से अपनाना।

इस प्रकार सतत विकास को इन तीन घटकों या आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज कई विकास एजेंसियां हरित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपना रही हैं, जो सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं ताकि मानव, अर्थव्यवस्था और समाज को संतुलित कर उनकी सीमाओं के अन्दर रह कर उपयोग करे एवं हर संभव संतुलन बनाये रखे व भविष्य को खतरे में न डाले, यह सुनिश्चित कराना ही सतत विकास है।

सतत विकास में शिक्षा – सतत विकास में शिक्षा की अवधारणा काफी हद तक पर्यावरण शिक्षा से विकसित हुई है, जिसने लोगों में अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने की मांग की है। सतत विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से समझौता किए बिना हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाने वाली शिक्षा से है । शिक्षा का उद्देश्य है की सतत विकास में निहित मूल्यों को सीखने के सभी पहलुओं और स्तरों में एकीकृत करने में सफल कराये । शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो मानव को सतत विकास के अनुकूल एवं उद्देश्यों के अनुरूप खरा उतारा जा सकता है । इस प्रकार, सतत विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा जगत में अनुसंधान को बढ़ावा देती है और मानव-निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकासात्मक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक एवं बुनियादी सुचना प्रदान करती है। मानव संसाधनों को मजबूत करने वाले कारको में से शिक्षा उन कारकों में से एक है, जो पूर्ण रूप से मानव के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि कर तार्किक क्षमता के साथ सतत विकास की रणनीति को विकसित व अपनाने का मार्ग प्रसस्त करने वाला कारक है । मानव संसाधन, सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण है इसलिए मानव संसाधन को मजबूत करना अति आवश्यक है और इस दिशा में शिक्षा को सशक्त करना आवश्यक है शिक्षा ही मानव संसाधन को सतत विकास के अनुरूप ढाल सकता है । शिक्षा सोचने की शक्ति देता है साथ ही शिक्षा एक सही दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार शिक्षा समस्त कारको में महत्वपूर्ण है और इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है की समयानुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे मजबूत करना जो अंतत: सतत विकास को सफल करने में सहायक होगा।

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को वैश्विक शिक्षा एजेंडे, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुसार संरेखित करने की प्रतिबद्धता के साथ तैयार किया गया है, जो 2030 तक देश के सभी लोगो के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराने पर कटिबद्ध है। यह नीति शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर आधारित है। परन्तु नीति की सफलता तभी संभव है जब शैक्षिक सुधार में आने वाली बाधाओं को दूर कर एवं इनमे सम्मिलित होने वाले सभी सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और साथ ही समुदाय सहित हितधारकों की सहभागिता स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से होगी।

सतत विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किये गए मुख्य सुधार

1. प्राथमिक विद्यालय से उच्च शिक्षण संस्थानों तक नए पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम की नयी समयावधि संबंधी में परिवर्तन की गई है।
2. भाषायी विविधता का संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओ के माध्यम से शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है।
4. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुवे है।
5. समावेशी विकास के अनुकूल उच्च शिक्षा में कई नए प्रावधान है।

नई नीति का मुख्य उद्देश्य ही है की एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमे भारतीय समाज की संस्कृति, भाषा, परम्पराओ एवं मूल्यों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार यह नीति समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली हो एवं जिसके माध्यम से एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमे ज्ञान, मूल्य एवं सतत विकास समाहित हो। इस नीति में प्राचीन शिक्षा से आधुनिक शिक्षा को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिसमे मुख्य रूप से पर्यवरण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। विद्यार्थी से लेकर शिक्षक तक सभी के लिए एक समावेशी एवं सभी के लिए सामान शिक्षा प्रणाली के रूप में लाने का प्रयास है।

निष्कर्ष – नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य रूप से सबकी पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य आदि बिन्दुओ पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो देश के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान हो एवं देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में विकसित करना है जिससे सभी नागरिक देश के परिवर्तन में अपना सकारात्मक योगदान दे सके । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में देश की शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाएगी साथ ही कौशल विकास को बढ़ाएगी, रूचिपरक एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में कुछ चुनौतिया सामने होगी जिसमे मुख्य रूप से नीति का उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन और संसाधन की आवश्यकता होगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यानुसार शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाना और विषयों की व्यापक श्रृंखला के साथ लागु करना एक बड़ी चुनौती होगी साथ ही नई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। परन्तु इन सभी चुनौतियो का समाधान संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Saini M. *et al* (**2021**) *"Analyzing the tweets to examine the behavioral response of Indian citizens over the approval of national education policy 2020"* International Journal of Educational Development, Elsevier, Vol. 82.
2. Hume T. & Barry J. **(2015)** *"Environmental Education and Education for Sustainable Development"* Internal Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, Second Edition.
3. Ashida A. (2023) *"The Role of Higher Education in Achieving the Sustainable Development Goals"* (eds.), Sustainable Development Disciplines for Humanity, Sustainable Development Goals Series, https://doi.org/10.1007/978-981-19-4859-6_5.
4. Sunny Y. (2021) *"National Education Policy 2020"* Economic & Political Weekly, Vol. 56, Issue 10.
5. Ahuja V. K. & Poddar D. (2022) *"National Education Policy 2020: The Road Ahead"*, Centre for Law, Public Policy and Governance National Law University and Judicial Academy, Assam, (eds.), ISBN: 978-81-954276-1-1.

****